



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 688]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2025 — भाद्र 7, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक LAW/717/2025. - चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है किपट्टा के अधीन प्रदान की गई औद्योगिक भूमि/भवन के समुचित विकास के लिए अंतरण के प्रावधानों को समय-सीमा से सम्बद्ध करना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन, एतद् द्वारा, "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,

- कंडिका 3.4.1.2 के खण्ड (अ) में शब्द समूह "परंतु आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार निवेश, वस्तुओं के उत्पादन, आवृत्त क्षेत्र के निर्माण आदि कार्यवाही पूर्ण न होने पर यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी" के स्थान पर शब्द-समूह "ऐसे प्रकरणों में कंडिका 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3 एवं 3.4.2.4 लागू नहीं होंगे" प्रतिस्थापित किया जाये।
- कंडिका 3.4.2.1 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"3.4.2.1 जिन प्रकरणों में आबंटित भू-खंड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन अनुसार बाउंड्री वाल छोड़कर कोई उत्पादन के लिए आवश्यक भवन का निर्माण न हुआ हो अर्थात् बाउंड्रीवाल/ उत्पादन कार्य हेतु अनुपयोगी भवन निर्मित हो तो भी, यदि भूमि आबंटन निरस्त न हुआ हो तो उनमें हस्तांतरण निम्नलिखित अनुसार किया जा सकेगा-

(अ) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि का 50% या उससे कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 50 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(ब) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि का 50% से अधिक किन्तु कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि से कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 100 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(स) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, ऐसे प्रकरण हस्तांतरण योग्य नहीं होंगे।"

3. कंडिका 3.4.2.2 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"3.4.2.2 जिन प्रकरणों में आबंटित भू-खंड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित भवन मद में प्रस्तावित परियोजना लागत का न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत तथा संयंत्र एवं मशीनरी मद में प्रस्तावित निवेश का न्यूनतम 25 (पच्चीस) प्रतिशत का निवेश होने पर उनमें हस्तांतरण निम्नलिखित अनुसार किया जा सकेगा-

(अ) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि का 50% या उससे कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 25 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(ब) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि का 50% से अधिक किन्तु कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि से कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 50 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(स) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, किन्तु कंडिका 3.1.1.1(2) में उल्लेखित समयावधि से कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 100 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(द) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1.1 (2) में उल्लेखित समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, ऐसे प्रकरण हस्तांतरण योग्य नहीं होंगे।"

4. कंडिका 3.4.2.3 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"3.4.2.3 जिन प्रकरणों में आबंटित भू-खंड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित भवन मद में प्रस्तावित परियोजना लागत का न्यूनतम 50 (पचास) प्रतिशत तथा संयंत्र एवं मशीनरी मद में प्रस्तावित निवेश का न्यूनतम 50 (पचास) का निवेश होने पर उनमें हस्तांतरण निम्नलिखित अनुसार किया जा सकेगा -

(अ) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि का 50% या उससे कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 20 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(ब) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि का 50% से अधिक किन्तु कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि से कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 45 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(स) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1 में उल्लेखित समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, किन्तु कंडिका 3.1.1.1(2) में उल्लेखित समयावधि से कम समय व्यतीत हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 100 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(द) जिन प्रकरणों में कंडिका 3.1.1.1 (2) में उल्लेखित समयावधि व्यतीत हो चुकी हो, ऐसे प्रकरण हस्तांतरण योग्य नहीं होंगे।"

5. कंडिका 3.4.2.4 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"3.4.2.4 जिन प्रकरणों में आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात् कार्यरत उद्योग/उद्यम, जिनमें आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो तथा निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 5 (पांच) प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

परन्तु, जिन प्रकरणों में आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो तथा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्योग/उद्यम, जिनमें आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार भूमि उपयोग की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हो, तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और उद्योग/उद्यम बंद हो तथा निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हुआ हो, उनमें हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील प्रब्याजी के 100 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।"

6. कंडिका 3.4.2.7 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-

"3.4.2.7 निरस्त भूखण्ड/शेड/ भवन/प्रकोष्ठ का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।

परन्तु इन नियमों में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 29-08-2025 से पूर्व प्रवृत्त कंडिका 3.4.2.1, 3.4.2.2, 3.4.2.3, 3.4.2.4 के अंतर्गत अंतरण की पात्रता रखने वाले प्रकरण में, अंतरण की अनुमति, हस्तांतरण की दिनांक पर लागू प्रभावशील भू-प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क के साथ, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् 3 माह की अवधि तक जारी की जा सकेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश कुमार पटेल, उप-सचिव.